MR. SPEAKER: Why don't we have separate rehabilitation centres for lepers, so that they could be taken care of?

SHRIMATI SHEILA KAUL: We have got...

MR. SPEAKER: You see all around some people begging, doing this and that and also calls for further action. We should at least forbid this type of people.

SHRIMATI SHEILA KAUL: We all have to see how this is...

MR. SPEAKER: I hope you will consider it.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Yes.

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, जन्म से ले कर मृत्यु तक इन विकलांगों को शिक्षा मंत्रालय से ले कर स्वास्थ्य मंत्रालय होते हुए रेल मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों की यात्रा करनी पड़ती है । इतनी लम्बी यात्रा के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है । ऐसी स्थिति में क्या सरकार पार्लियामेंट की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायेगी जो मानीटरिंग और कोआर्डिनेशन का काम देखे और सरकार को संचालन में मदद करे ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं क्योंकि यह एक बहुत बड़ा भारी प्रोग्राम शुरू कर दिया है इस विषय में इसलिए पार्लियामेंटरी कमेटी की मैं आवश्यता नहीं समझती । वैसे आप मालिक हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री जी ने अपने लम्बे चौड़े स्टेटमेंट में बताया कि गर्भवती माताओं, बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौषक तत्व दिये जाते हैं और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं खासतौर से गन्दी बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में । तो मैं जानना चाहता हूं कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जिनका जिक्र आपने अपने स्टेटमेंट में किया है, इन शहरों में अनुसूचित जातियों के लिए जो यह कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं स्वच्छिक संस्थानों द्वारा ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान या ग्राण्ट देने का मंत्री जी ने कोई क्राइटीरिया बनाया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्रीमती शीला कौल : हम मदद देते हैं उन संस्थाओं को जो हमसे मांगती हैं और काफ़ी तादाद में हम ऐसी संस्थाओं को पैसा बांटते भी हैं । 1980-81 में .....

अध्यक्ष महोदय : वह क्राइटीरिया पूछते हैं । कोई मापदण्ड हो तो वह बताइये ।

श्रीमती शीला कौल : जो आर्गेनाइजेशन्स इस तरह का काम करती आई हैं, कुछ अर्से तक जिन्होंने लगातार काम किया है और जिनके बारे में हमें जानकारी होती है कि यह सही आर्गेनाइजेशन्स हैं और सही काम करती हैं और कुछ अर्से से कर रही हैं तो उनको हम देते हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सही आर्गेनाइजेशन तो सभी मानी जायेंगी जो भी सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र देंगी ।

श्रीमती शीला कौल : ऐसी बहुत सी ऐप्लीकेशन्स स्टेट गवर्नमेंट की मार्फत आती हैं और जब वह ओ० के० कर देती हैं तभी हम उनको देते हैं ।

Railway Apprenticeship Scheme

*372. SHRI M. M. LAWRENCE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the steps taken, so far by Government regarding long pending demand of Engineering Graduates and

Diploma Holders who have undergone and completed Railway Apprenticeship scheme, for absorption in suitable jobs and for fixation of some percentage of quota of vacancies for this purpose?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Engineering Graduates and Diploma Holders who have completed Apprenticeship on the Railways under the Apprenticeship Act may appear in the selections held by the Railway Service Commissions for recruitment on the Railways along with other open market candidates if they fulfil the age and other conditions for such recruitment. The request for directly absorbing them in suitable jobs on the Railways and fixation of some percentage of quota of vacancies for this purpose has been considered but it has not been possible to agree to the same.

SHRI M. M. LAWRENCE: Sir, earlier, some clerks who have completed the training were absorbed. Likewise, I would like to know why the Government is hesitating to absorb these people also in the service as having spent so much time and as so much money also has been spent for the training.

SHRI MALLIKARJUN: Sir, as per the Act of Apprenticeship, apprenticeship to engineering graduates and diploma graduates is being offered in the Indian Railways. But they are not supposed to be absorbed. There is a procedure in this regard. These Engineering graduates and diploma holders after apprenticeship have to go through the Railway Service Commission. Whenever vacancies are available, after passing through the Railway Service Commission, they will be absorbed. The hon. Member has rightly pointed out that in April, 1977 the then Minister has absorbed some of the clerical non-artisans who had been given training of apprenticeship. But later one Shri T. C. Peter who was also an Engineering Graduate and who had the apprenticeship training, filed a writ in the Madras High Court, Now the case is sub judice.

SHRI M. M. LAWRENCE: Will the Government consider at least absorbing the present people who have undergone training?

SHRI MALLIKARJUN: This is what I have said. As per the Apprenticeship Act itself after apprenticeship those people cannot be absorbed directly. We have Railway Service Commission. They have to go through it.

It is Railways who have given them training and who have been given the opportunity to work on the shop floor. Therefore, we will be happier to consider the Apprentice Engineering Graduates who take training on the Railway work floor than a fresh man who has simply come through the Railway Service Commission without any training.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सभा-पटल पर रखे गए विवरण को देखने से पता चलता है कि रेलवे जो एप्रेनटिसशिप देती है, उस पर वह कुछ खर्च करती है, लेकिन जब एप्रेनटिसशिप की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, तो उन लोगों को भी फ्रैश पास किए हुए उम्मीदवारों के साथ एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है और कहा जाता है कि वे भी रेलवे सर्विस कमीशन के सामने जाएं। रेलवे एक व्यक्ति को पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लेने के बाद एप्रेनटिसशिप में लेती है, वह हर आदमी को नहीं लेती है, और वह उसकी ट्रेनिंग पर खर्च करती है। उसके बाद यदि उसको भी फ्रैश उम्मीदवारों के साथ काम्पीटीशन फ़ेस करना है, तो यह बात समझ में नहीं आती कि रेलवे उस पर खर्च क्यों करती है। मैं यह जानना

चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की ट्रेनिंग पर ख़र्च किया गया है और जिस पर ख़र्च नहीं किया गया है, क्या उन दोनों के बारे में अलग अलग विचार होगा या एक ही तरह से विचार होगा ।

श्री मल्लिकार्जुन : जब रेलवे एक इंजीनियरिंग ग्रैजुएट को स्टाइपेंड दे कर ट्रेनिंग देती है, तो वह और मज़बूत बन जाता है और इस लिए जब वह रेलवे सर्विस कमीशन के सामने जाता है, तो वह आसानी से पास हो कर हमारे पास आ सकता है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जब रेलवे एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देती है, उस पर पैसा खर्च करती है, तो बाद में उसको फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ काम्पीटीशन में बैठने के लिए क्यों कहा जाता है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जब रेलवे सर्विस कमीशन के सामने फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रैजुएट एपीयर होते हैं, तो उनके कम्पेरिजन में एप्रेनटिसशिप करने वाले इंजीनियरिंग ग्रैजुएट आसानी से पास हो सकते हैं और वे ले लिए जाते हैं । जहां तक खर्च का सवाल है, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा थ्रू आउट-इंडिया हर डिपार्टमेंट में 1962 में एप्रेनटिसशिप एक्ट लागू किया गया था । वह केवल रेलवे तक परिमित नहीं है । उस कानून में यह नहीं बताया गया है कि जो लोग एप्रेनटिसशिप करते हैं, उनको इमीडिएट्ली एबजार्ब कर लिया जाए । एप्रेनटिसशिप तो देते हैं, लेकिन अगर वैकेन्सी हो, तो प्रेसीड्युर के मुताबिक आने पर उन लोगों को एबजार्ब कर लेते हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : पहले एक व्यक्ति का सिलैक्शन करते हैं और उस पर पैसा खर्च करते हैं । उसके बाद भी उसको ओपन काम्पीटीशन में फ्रेश आदमियों के साथ आना पड़ता है । (व्यवधान) ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं बता रहा हूं कि जिस ग्रैजुएट पर रेलवे का पैसा खर्च हुआ, जिसको रेलवे की ट्रेनिंग मिला उसको खुशी से लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : पैसे अपनी पर खर्च होते हैं । कोई ख़ास बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आप भी यही कह रहे हैं ।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : ऐप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग जो टैक्नीकल लोग हैं, ओवरसीयर्स हैं, टैक्नीकल ग्रेजुएट्स हैं, उन को दी जाती है । अब यह कहना कि उन को ट्रेनिंग दी गई है इस लिए डायरेक्ट क्यों नहीं रख लेते —ऐसा नहीं है, उन को भी रेलवे सर्विस कमीशन के सामने एपियर होना होगा । वहां उन का केस काफ़ी आसान होता है, उन को प्रिफरेंस भी मिल जाता है, लेकिन उसी के थ्रू उन को आना होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेण्ट का कहीं भी लॉ नहीं है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : फिर उन पर पैसा क्यों खर्च करते हैं ?

श्री केदार पान्डे : ट्रेनिंग से उन के सिलैक्शन में उन को सुविधा हो जाती है, उन की नींव मज़बूत होती है ।

SHRI INDRAJIT GUPTA: Sir, the Minister should have clarified that under the Central Apprentices Act, there is a statutory obligation on the part of employers to give training to a certain number of apprentices. But there is no obligation, unfortunately, on them to provide for jobs to the apprentices. Now, you did not tell that.

श्री केदार पांडे : मैंने पहले ही कहा है कि उन को नौकरी देना आबलीगेशन नहीं है ।

They should appear before the Public Service Commission irrespective of the fact whether we can amend the Apprentices Act or not.

SHRI INDRAJIT GUPTA: My question is in view of everything the Minister has stated, whether any clear cut advice or direction has been given by the Railway Ministry or the Railway Board to the Railway Service Commissions to give preference to those candidates who have already passed the apprenticeship course.

Number 2. Can he tell us what percentage of candidates who have completed the railway training course and appeared before the Railway Service Commission, have actually been absorbed in the services?

SHRI MALLIKARJUN: I have already clarified about the Apprenticeship Act. It is needless to re-emphsise it. So far as the other two aspects of the question are concerned, the Railway Board does not interfere with the functioning of the Railway Service Commission.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Do you give preference? Can you tell me?

SHRI MALLIKARJUN: You have patience to listen to me. We do not interfere with them. But when a person who has been trained in the railways appears before the Commission, naturally he will have a better chance of getting through.

Number 2. As for the question which the hon. Member, Mr. Yadav had earlier asked, we have spent the money in all departments of the Government of India. Stipend is being paid to these apprentices in all Departments and not in Indian Railways alone.

SHRI INDRAJIT GUPTA: My second part is this. What is the percentage of those apprentices who have applied through the Railway Service Commission and who have been actually absorbed in the services?

SHRI MALLIKARJUN: At the moment, I do not have the percentage of apprentices, who have appeared before the Railway Service Commission.

Vocational Education in Tribal Areas

*373. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether employment-oriented vocational and technical education is being imparted in Primary and Higher Secondary Schools in areas predominantly inhabited by tribals and Scheduled Castes; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI) SHEILA KAUL): (a) and (b). No specifically employment-oriented vocational or technical education is being imparted at the Primary level either in the areas predominantly inhabited by Scheduled Castes or Scheduled Tribes or elsewhere. In regard to the Higher Secondary stage, a beginning has been made in some of the States, among those that have accepted the 10+2 pattern, to provide for vocational courses. Since it will be necessary to have area-wise surveys to assess the specific needs in the respective areas and since teachers will have to be trained and equipment provided, it will take some time before such vocational courses, either in areas predominantly inhabited by Scheduled Castes or Scheduled Tribes or in other areas to become available on an extensive scale.

SHRI ARJUN SETHI: Mr. Speaker Sir, my question relates to employment-oriented vocational and technical education exclusively imparted in tribal and Scheduled Caste areas. The hon. Minister has stated in her statement that no steps have been taken exclusively for these people. It is a fact that in spite of best of efforts by the Government at the Centre as well